आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(5) के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत, “संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न” संबंधित कर-वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने के अंदर (यानी 31 दिसंबर तक) या मूल्यांकन (असेसमेंट) पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि, देर से रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी नौ महीने है, इसलिए तय सीमा के अंत में देर से रिटर्न फाइल करने वाले करदाता को रिटर्न में संशोधन करने का कोई अवसर नहीं मिलता है।

इस समस्या को हल करने के लिए, धारा 263(5) को वित्त अधिनियम, 2026 के द्वारा 1-अप्रैल-2026 से बदल दिया गया है, ताकि संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को संबंधित कर-वर्ष के समाप्त होने से नौ महीने से बढ़ाकर 12 महीने या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, कर दिया गया है। इससे संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न को संबंधित कर-वर्ष (यानी 31 मार्च) के समाप्त होने से 12 महीने तक फाइल किया जा सकता है।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2026 ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 428(b) के अंतर्गत फीस लगाना भी शुरू कर दिया है, जहाँ संबंधित कर-वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने बाद संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न फाइल की जाती है तो फीस इस प्रकार होगी:

- 1,000 रुपये, जहाँ कुल आय 5 लाख से ज़्यादा नहीं है; और
- 5,000 रुपये, दूसरे अन्य मामलों में।

क्या आप जानते हैं ?

वित्त अधिनियम, 2026 के द्वारा “संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न” फाइल करने की समय सीमा को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

Released on 27th April, 2026